भारत संघ और अन्य

बनाम

दिलीप कुमार सिंह

(सिविल अपील संख्या 2466-2467/2015)

26 फरवरी, 2015

[न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर और न्यायाधिपति आर. एफ. नरीमन]

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 - धारा 47 का प्रावधान - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मचारी स्थायी रूप से अक्षम - सेवा से मुक्त - रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को यह कहते हुए याचिका की अनुमति दी धारा 47 (सीआरपीएफ को धारा 47 की कठोरता से छूट) के प्रावधानों के तहत जारी दिनांक 10.9.2002 केवल धारा 47 की उप-धारा (2) के संदर्भ में लागू होगा, न कि धारा के तहत प्रावधानों के मद्देनजर पूरे प्रावधान पर। 73 (3) और (4) - अपील पर, माना गया: धारा 47 का प्रावधान पूरे प्रावधान पर लागू होगा, केवल उसकी उपधारा (2) पर नहीं - प्रावधान की व्याख्या धारा 73 के संदर्भ में नहीं की जा सकती - एक प्रावधान इससे आगे नहीं बढ़ता वह प्रावधान जिसका यह एक परंतुक है - इसके अलावा, धारा 47 अग्रणी और मूल प्रावधान है और धारा 73 एक अधीनस्थ है और मशीनरी प्रावधान धारा 47 मान्य होगा - छूट समझदार अंतर पर आधारित है और मांगी गई वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध है प्राप्त किया जाना चाहिए अर्थात किसी प्रतिष्ठान में किए जाने वाले "कार्य का प्रकार" - इसलिए, यह भेदभावपूर्ण भी नहीं है - कर्मचारी को सेवा से उचित रूप से मुक्त किया गया था - सेवा कानून।

क़ानून की व्याख्या - किसी क़ानून के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए - दो वर्गों के बीच संघर्ष के मामले में, यदि समाधान संभव नहीं है, तो यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि कौन सा अग्रणी है और कौन सा अधीनस्थ प्रावधान है और किसको दूसरे को रास्ता देना चाहिए ।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने माना:

1. धारा 47 को समग्र रूप से पढ़ना है और समग्र रूप से पढ़ने पर इसके प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यह किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए "कार्य के प्रकार" पर लागू होगा और इसलिए, दोनों वितरणों पर लागू होगा। सेवा में पद में कमी के साथ-साथ पदोन्नति भी शामिल है। धारा 47 का प्रावधान "इस धारा" की बात करता है। इस परंतुक पर लागू शाब्दिक नियम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह संपूर्ण धारा पर लागू होगा, अन्यथा प्रयुक्त शब्द "यह उपधारा" होते। [पैरा 12 और 21] [892-एफ; 893-सी-डी]

2.1. यह सही नहीं है कि धारा 73(3) और (4) के मद्देनजर धारा 47 का प्रावधान केवल धारा 47 की धारा (2) का प्रावधान है। किसी क़ानून के प्रावधानों को एक साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, फिर जहां दो वर्गों के बीच संघर्ष है और दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता है, तो यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा प्रमुख प्रावधान है और कौन सा अधीनस्थ प्रावधान है, और कौन सा दूसरे को रास्ता देता है। वर्तमान मामले में, धारा 47 "प्रमुख प्रावधान" है और धारा 73 "अधीनस्थ प्रावधान" है। इसके अलावा धारा 47 एक सकारात्मक और स्पष्ट प्रावधान है। इसका कारण यह है कि, धारा 47 धारा 73 के विपरीत समग्र रूप से धारा 47 की विषय वस्तु से छूट देने वाला एक मूल प्रावधान है, जो कि केवल एक मशीनरी प्रावधान है जिसके द्वारा धारा 47 के तहत की गई

अधिसूचनाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी हैं। {पैरा 15, 16 और 19] [893-एच; 894-ए-सी: 896-एच; 897-ए-बी]

श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम सेठी मुकंद कंवर और दो अन्य, 1965 (1) एस. सी. आर. 726-पर निर्भर थे।

पेटेंट एजेंटों और अन्य संस्थान बनाम जोसेफ लॉकवुड, 1894 ए.सी. 347; प्रोजेक्ट ब्लू स्काई इंक. बनाम ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, 153 एएलआर 490 - संदर्भित।

2.2. एक परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं जाता जिसके लिए वह अनुमोदित है। इसलिए, सुनहरा नियम यह है कि प्रावधान समेत पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए कि वे परस्पर एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण हो। [पैरा 20] [897-8-सी]

द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ 1976 (1) एससीआर 277 =(1976) 1 एसईसी 128 - पर भरोसा किया गया।

3. किन तथ्यों और परिस्थितियों में सरकार किसी प्रतिष्ठान में काम के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करती है, यह स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है जिसके लिए लाभकारी कानून बनाया गया है, साथ ही कुछ प्रतिष्ठानों को एक हिस्से से छूट देने की आवश्यकता को संतुलित करने के साथ-साथ अधिनियम के संपूर्ण प्रावधान. वास्तविक निर्माण पर, यह स्पष्ट है कि कानून ने सरकार को किसी भी प्रतिष्ठान को न केवल पदोन्नति के लिए बल्कि सेवा से समाप्ति और रैंक में कमी के लिए भी अधिनियम की कठोरता से छूट देने की शक्ति दी है। [पैरा 23] [899-सी-ई]

4. धारा 47 और अध्याय VIII के सीमांत नोट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें धारा 47 आती है, यानी "गैर-भेदभाव", यह स्पष्ट है कि धारा 47 का विचार उन कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव करना नहीं है, जिन्होंने सेवा के दौरान विकलांगता हासिल कर ली है। यह स्थापित कानून है कि भेदभाव को अमूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता - वर्गीकरण का सिद्धांत भेदभाव के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सहायक है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाला कोई समझदार अंतर है, तो प्रावधान को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, एक छूट प्रावधान इस तरह के वर्गीकरण पर आधारित है और किसी भी प्रतिष्ठान को सेवा न देने या रैंक में कमी करने या पदोन्नति न देने से छूट देने का उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है जिसे हासिल करना चाहा गया है, अर्थात्, "कार्य का प्रकार" किया जाता है। किसी प्रतिष्ठान में ऐसा हो सकता है कि किसी विकलांग कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं और/या पदोन्नति से इनकार किया जा सकता है। [पैरा 22] [898-ई-एच, 899-ए]

5. यह कहना सही नहीं है कि 10 सितंबर, 2002 की छूट अधिसूचना इस कारण से लागू नहीं होगी कि दुर्घटना 2002 से पहले हुई थी। प्रासंगिक तारीख, सेवा से मुक्ति की तारीख है, न कि वह तारीख जिस पर विकलांगता उत्पन्न होती है, क्योंकि धारा 47 किसी प्रतिष्ठान को उस कर्मचारी की सेवा से वंचित करने से रोकती है जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है। चूंकि सेवा 1 जुलाई, 2011 को समाप्त कर दी गई थी (जो कि छूट अधिसूचना की तारीख के काफी समय बाद है), अधिसूचना लागू होगी। [पैरा25] [899-एच; 900-ए.बी]

6. भेदभाव की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई है, और इस न्यायालय के समक्ष उठाई गई याचिका में विवरण का अभाव है और इस कारण से भी इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 28] [902-बी]

कुणाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य 2003 (1) एससीआर 1059=(2003) 4 एससीसी 524- प्रतिष्ठित। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू एवं अन्य 2003 (2) एससीआर 495 =(2003) 3 एससीसी 338 - अनुपयुक्त ठहराया गया

मो. शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2010 (3)एस सी आर 911=(2010)4 एस सी सी 653 : एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 (2) एस सी आर 644 = (1994)3 एस सी सी 1 उद्ध्रत किया ।

वाद कानून संदर्भित

2010(3)एस सी आर 911	उद्धृत किया	पैरा 6
1994(2)एस सी आर 644	उद्धृत किया	पैरा 6
1894 ए सी 347	संदर्भित	पैरा 16
153 ए एल आर 490	संदर्भित	पैरा 17
1965(1)एस सी आर 726	भरोसा किया	पैरा 18
1976(1)एस सी आर 277	भरोसा किया	पैरा 20
2003(2)एस सी आर 495	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 23
2003(1)एस सी आर 1059	विशिष्ट	पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2466-2467/2015

2004 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 30278 के साथ 2011 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 42101 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.01.2014 से।

पी एस पटवालिया, बी बी साहनी, नताशा विनायक, तुषारबख्शी, सुषमा सूरी अपीलार्थियों के लिए

महाबीर सिंह, आयुष चौधरी, गौतम अवस्थी उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति आर एफ नरीमन

1. अनुमति दे दी गई।

2. ये अपीलें विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "1995 अधिनियम") की धारा 47 में निहित प्रावधान की व्याख्या के बारे में एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

1 जनवरी 1998 को, प्रतिवादी को सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती किया गया था। ड्यूटी के दौरान, 19 अक्टूबर, 2001 को जब वह नाइटगार्डों की जांच के लिए निकले थे, तब उनकी रीढ़ की हड्डी और पैरों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद, उन्हें विभिन्न अस्पतालों में विशेष उपचार प्रदान किया गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ और अंततः, एक मेडिकल बोर्ड ने 22 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादी को पीईई-5 के रूप में वर्गीकृत किया यानी एक व्यक्ति जो स्थायी रूप से अक्षम है और कहा कि वह 100% है। विकलांगता और सिफारिश की गई कि उन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया जाए। 27 अक्टूबर, 2004 को, प्रतिवादी को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि यदि कोई हो, तो उसके खिलाफ अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य करने का प्रस्ताव। कारण बताओ नोटिस के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के बजाय, प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 30278/2004 दायर की। 19 जनवरी, 2005 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को कोई भी आदेश

पारित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दी गई रिपोर्ट के अनुसार।

4. स्थगन आवेदन को संशोधित करने वाले आदेश के अनुसार, 1 जुलाई, 2011 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी को सेवा से मुक्त कर दिया गया और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 38 के तहत स्वीकार्य अमान्यता पेंशन दी गई। प्रतिवादी ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए दूसरी रिट याचिका संख्या 42101/2011 दायर की।

5. 8 जनवरी के आक्षेपित निर्णय द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 47 के निर्माण पर कहा कि जहां तक सीआरपीएफ का संबंध है, धारा 47 के तहत 10 सितंबर 2002 को एक अधिसूचना जारी की गई, (सीआरपीएफ को धारा 47 की कठोरता से छूट दी गई)) को केवल धारा 47(2) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि छूट का प्रावधान केवल पदोन्नति पर लागू होगा, प्रतिवादी को सेवा में जारी रखने पर नहीं। परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 2011 के आदेश को रद्द कर दिया गया और संघ को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को सेवा में माना जाए और जब तक कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, तब तक उसे किसी उपयुक्त पद पर या अतिरिक्त पद पर समायोजित किया जाए। इनमें से जो भी पहले हो।

6. श्री पी.एस. पटवालिया को पता चला कि भारत संघ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 1995 का अधिनियम हमारे सामने रखा है। उन्होंने धारा 33, धारा 47 और धारा 73 का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि धारा 47 का अंतिम प्रावधान पूरी धारा पर लागू होगा, न कि केवल उपधारा (2) पर, जैसा कि प्रावधान की भाषा से स्पष्ट है, जिसमें "यह धारा" शब्दों का उपयोग किया गया है। "

न कि "यह उपधारा"। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं है, इसलिए धारा 73(3) और 73(4) का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है, जो धारा 47 के प्रावधान को "धारा 47 की उप-धारा (2) के प्रावधान" के रूप में संदर्भित करता है। ". उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की योजना आक्षेपित निर्णय से परेशान होगी क्योंकि धारा 33 और धारा 47 एक ही आधार को कवर करती हैं - धारा 33 नियुक्ति से पहले लागू होती है और धारा 47 नियुक्ति के बाद लागू होती है। उन्होंने पैराग्राफ 179 में मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य और अन्य (2010) 4 एससीसी 653 का हवाला दिया, जो निर्णय निर्माण के शाब्दिक नियम और एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एससीसी 1 को पैराग्राफ 238 और 239 में संदर्भित करता है। प्रस्ताव कि अदालतें कैसस ऑमिसस की आपूर्ति नहीं कर सकतीं।

7. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महाबीर सिंह ने हमारे सामने तर्क दिया है कि आक्षेपित निर्णय सही है क्योंकि 1995 अधिनियम विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक लाभकारी कानून है और इसलिए, एक व्यापक निर्माण क्रम में है।

8. उन्होंने तर्क दिया कि धारा 47 और 73 को सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझा जाना चाहिए और इस तरह समझा जाना चाहिए, धारा 73 धारा 4 7 पर प्रकाश डालती है और प्रावधान को केवल उसकी उपधारा (2) पर लागू करती है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी परिस्थिति में एक विकलांग व्यक्ति, जब वह अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त कर लेता है, तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ होगा। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि 10 सितंबर, 2002 की छूट अधिसूचना तथ्यों पर लागू नहीं होगी क्योंकि विकलांगता अधिसूचना से पहले हुई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी के खिलाफ भेदभाव था क्योंकि अन्य विकलांग लोगों की सेवा समाप्त नहीं की गई थी।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। 1995 अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:-

"एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी करने के लिए एक अधिनियम जबकि 1 से 5 दिसंबर, 1992 को बीजिंग में एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को लॉन्च करने के लिए बैठक में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी औरसमानता पर उद्घोषणा को अपनाया गया था। और चूँकि भारत उक्त उद्घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है; और चूँकि उपरोक्त उद्घोषणा को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा जाता है।"

10. धारा 33, 47 और 73(3) और (4) यहां नीचे दी गई हैं:

"33. पदों का आरक्षण - प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए कम से कम तीन प्रतिशत रिक्तियां नियुक्त करेगी, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतिशत निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा-

(1) अंधापन या कम दृष्टि;

(ii) श्रवण हानि;

(iii) लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी,

प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में:

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी विभाग या प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी

शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

47. सरकारी रोजगार में भेदभाव न होना.-

(1) कोई भी प्रतिष्ठान सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी को छूट नहीं देगा, या उसका रैंक कम नहीं करेगा:

बशर्ते, यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद अपने पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि ऐसा करना संभव न हो। कर्मचारी को किसी भी पद पर समायोजित करने के लिए, उसे एक अतिरिक्त पद पर तब तक रखा जा सकता है जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो।

(2) किसी व्यक्ति को केवल उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा:·

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रख सके। किसी भी प्रतिष्ठान में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दें।

73. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति.-

(3) धारा 33 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना, धारा 47 की उप-धारा (2) के प्रावधान, धारा 27,

धारा 30, धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई प्रत्येक योजना , धारा 42, धारा 43, धारा 67, धारा 68 और उप-धारा (1) के तहत इसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जबकि इसका सत्र चल रहा है। तीस दिनों की कुल अवधि जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि सत्र के तुरंत बाद या उपरोक्त क्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं, अधिसूचना या योजना, दोनों सदन इस बात पर सहमत हैं कि नियम, अधिसूचना या योजना नहीं बनाई जानी चाहिए, नियम, अधिसूचना या योजना उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या कोई प्रभाव नहीं डालेगी, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण, जैसा भी मामला हो, उस नियम, अधिसूचना या योजना के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा धारा 33 के प्रावधानों के तहत बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना, धारा 47 की उप-धारा (2) के तहत बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना, धारा 27, धारा 30, धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत बनाई गई प्रत्येक योजना , धारा 42, धारा 43, धारा 67, धारा 68, और उप-धारा (1) के तहत इसके द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहां यह शामिल है दो सदनों का या जहां ऐसी विधायिका में उस सदन से पहले एक सदन होता है।"

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री महावीर सिंह यह कहने में सही हैं कि यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर एक उद्घोषणा के अनुसार पारित एक लाभकारी कानून है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। हालाँकि, हम पाते हैं कि इसके बाद दिए गए कारणों से आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

12. यह देखा जाएगा कि धारा 47 का परंतुक "इस धारा" की बात करता है। इस परंतुक पर लागू शाब्दिक नियम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह संपूर्ण धारा पर लागू होगा, अन्यथा प्रयुक्त शब्द "यह उपधारा" होते। इसके अलावा, इसकी भाषा प्रावधान धारा 33 में निहित प्रावधान की भाषा के समान है। दोनों प्रावधान किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए "कार्य के प्रकार" को ध्यान में रखते हुए छूट दिए जाने की बात करते हैं। यह स्पष्ट है कि हमारे सामने सशस्त्र बलों या सीआरपीएफ द्वारा किए गए "कार्य के प्रकार" को देखते हुए, विकलांग व्यक्तियों को पूर्व-नियुक्ति पर उनके लिए कोई आरक्षण नहीं मिल सकता है, यदि छूट दी गई है, तो इसका सीधा सा कारण यह है कि विकलांग व्यक्तियों को (जैसा कि धारा 2(टी) के तहत परिभाषित किया गया है, इसका मतलब है कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से कम विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति देश की रक्षा में आवश्यक सेवा के लिए पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति हो सकता है। यह स्पष्ट है कि, यदि नियुक्ति के समय चरण में, विकलांग व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित पदों पर रिक्तियों की आवश्यकता नहीं है, समान रूप से सेवा के दौरान विकलांगता से पीड़ित होने के बाद, एक व्यक्ति स्वयं उसी कारण से राष्ट्र की रक्षा में वह कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता है जो उससे अपेक्षित है, जिससे सेवा से अपनी बर्खास्तगी को उचित ठहराते हुए।

13. प्रावधान का संदर्भ "कार्य का प्रकार" है। यह स्पष्ट है कि इस संदर्भ को देखते हुए, जहां तक "पदोन्नति" का संबंध है, छूट का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जहां तक "वितरण" का संबंध है, कोई छूट नहीं है।

14. उच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क यह था कि उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत, यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे एक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई कि जो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त कर लेता है, उसे किसी भी परिस्थिति में उसकी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क इस कारण से भ्रामक है कि उप-धारा (1) सेवा के साथ-साथ रैंक में कमी से संबंधित है। तर्क यह है कि दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए धारा 47(1) के तहत किसी कर्मचारी की सेवाओं को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें यह ध्यान देने में विफल रहता है कि जहां तक रैंक में कमी का सवाल है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक रैंक में कमी का सवाल है, अगर छूट दी जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि जहां तक सेवा से छूट का सवाल है, ऐसी छूट क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि दोनों अधिनियम की धारा 47(1) में निहित हैं।

15. अब हम उस बात पर आते हैं जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई थी और हमारे सामने सबसे जोरदार तरीके से बहस की गई थी। यह कहा गया था कि धारा 73(3) और (4) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रावधान केवल धारा 47 की उप-धारा (2) का एक प्रावधान है और इसलिए इसे केवल ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए। इसके फिर से दो उत्तर हैं।

16. यह सर्वविदित है कि किसी क़ानून के प्रावधानों को एक साथ सौहार्दपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है तो यह स्थापित कानून है कि जहां

दो धाराओं के बीच संघर्ष है, और आप दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा प्रमुख प्रावधान है और कौन सा अधीनस्थ प्रावधान है, और किसे रास्ता देना चाहिए अन्य। कानून का यह कथन इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट एजेंट्स एंड अन्य बनाम जोसेफ लॉकवुड, 1894 ए.सी. 347, 360 लॉर्डहर्शेल, एलसी में पाया जाना है, जो इस प्रकार है:-

> "ठीक है, एक ही अधिनियम में पाए जाने वाले दो खंडों के बीच कभी-कभी संघर्ष होता है। आपको यथासंभव प्रयास करना होगा और उन्हें सुलझाना होगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा प्रमुख प्रावधान है और कौन सा अधीनस्थ प्रावधान है, और जिसे दूसरे को रास्ता देना होगा।"

17. इस निर्णय का बाद में प्रोजेक्ट ब्लू स्काई इंक. बनाम ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, 153 एएलआर 490 में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में पालन किया गया है:

> "एक विधायी साधन को प्रथम दृष्टया आधार पर समझा जाना चाहिए कि इसके प्रावधानों का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण लक्ष्यों को प्रभावित करना है। जहां विशेष प्रावधानों की भाषा से संघर्ष उत्पन्न होता प्रतीत होता है, जहां तक संभव हो, अर्थ को समायोजित करके संघर्ष को कम किया जाना चाहिए प्रतिस्पर्धी प्रावधानों के उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो सभी वैधानिक प्रावधानों की एकता को बनाए रखते हुए उन प्रावधानों के उद्देश्य और भाषा को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करेगा। संघर्ष प्रावधानों को सुलझाने के लिए अक्सर अदालत की आवश्यकता होगी"यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा प्रमुख प्रावधान है और

कौन सा अधीनस्थ प्रावधान है, और किसे दूसरे को रास्ता देना चाहिए"। केवल प्रावधानों के पदानुक्रम का निर्धारण करके ही कई मामलों में प्रत्येक प्रावधान को वह अर्थ देना संभव होगा जो वैधानिक योजना की एकता को बनाए रखते हुए उसके उद्देश्य और भाषा को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है।" (पृष्ठ 509-510 पर)

18. इसी तरह की परिस्थितियों में, श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम सेठानी मुकंद कंवर और दो अन्य, 1965 (1) एससीआर 726 में, एक सवाल उठा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 2 (डी) को कैसे सुसंगत बनाया जाएगा। प्रभाव धारा 2(डी) का, जो एक बचत खंड है, वह है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान कानून के संचालन द्वारा स्थानांतरण पर लागू होंगे। जबकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 5 संपत्ति के हस्तांतरण को परिभाषित करती है, जिसका उद्देश्य पार्टियों के कृत्यों द्वारा किए गए हस्तांतरणों को लेना है। इसलिए, नीलामी बिक्री, कानून के संचालन से होने वाले हस्तांतरण, धारा 2(डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 100 (बाद वाला भाग) के दायरे में होगी। (धारा 100 में प्रावधान है कि किसी भी संपत्ति के खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, जिसे ऐसी संपत्ति विचार के लिए और आरोप की सूचना के बिना हस्तांतरित की गई है।) धारा 2 (डी) को धारा 5 पर प्रबल माना गया क्योंकि यह है एक "सकारात्मक प्रावधान" जो "स्पष्ट" है। इस न्यायालय ने कहा:

"हालाँकि, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 5 में निहित प्रावधानों के कारण यह स्थिति कुछ हद तक जटिल हो गई है। धारा 5 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि निम्नलिखित धाराओं में "संपत्ति का हस्तांतरण" का अर्थ एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा जीविकोपार्जन किया जा सकता है। व्यक्ति, वर्तमान या भविष्य

में, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करता है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की सभी धाराओं में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "संपत्ति हस्तांतरण" की परिभाषा का उद्देश्य है पार्टियों के हस्तक्षेप और नीलामी-बिक्री के कृत्यों से प्रभावित स्थानान्तरण स्पष्ट रूप से ऐसा कार्य नहीं है। इसलिए, धारा 5, नीलामी बिक्री को धारा 100 के दायरे से पूरी तरह से बाहर करती प्रतीत होती है। यह परिणाम प्रावधान के अनुरूप प्रतीत होगा अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था क्योंकि पार्टियों के कार्य द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून के कुछ हिस्सों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन समझा गया था। पढ़ने से यही स्थिति उभरती है धारा 5 की प्रस्तावना के साथ युग्मित; और इससे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इन दो असंगत स्थितियों में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए।

हमारी राय में, धारा 2(डी) में निहित सकारात्मक प्रावधान धारा 5 द्वारा निर्धारित "संपत्ति के हस्तांतरण" की परिभाषा पर हावी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, परिभाषा का उद्देश्य हस्तांतरण के उस वर्ग को इंगित करना है जिस पर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का इरादा है; लेकिन इस प्रकार की परिभाषा धारा 2(डी) द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों में निहित स्पष्ट और सकारात्मक दिशा को खत्म नहीं कर सकती है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, धारा 2(डी) द्वारा अधिनियमित बचत खंड का परिणाम इस तथ्य पर जोर देना है कि धारा 57 के प्रावधान और अध्याय IV में निहित

प्रावधानों को कानून के संचालन द्वारा स्थानांतरण पर लागू होना चाहिए। धारा 5 द्वारा निर्धारित परिभाषा के प्रभाव को प्रकट करने के लिए ऐसा सकारात्मक प्रावधान नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि धारा 5 द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुरूप नहीं, धारा 100 का उत्तरार्द्ध भाग होना चाहिए नीलामी बिक्री को शामिल माना जाता है।"(पेज 733 पर)

19. इन दो निर्णयों के संदर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 47 "प्रमुख प्रावधान" है और धारा 73 "अधीनस्थ प्रावधान" है। इसके अलावा, धारा 47 एक सकारात्मक और स्पष्ट प्रावधान है। इसका कारण यह है कि, धारा 47 धारा 73 के विपरीत समग्र रूप से धारा 47 की विषय वस्तु से छूट देने वाला एक मूल प्रावधान है, जो केवल एक मशीनरी प्रावधान है जिसके द्वारा धारा 47 के तहत की गई अधिसूचनाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी हैं।

20. समान रूप से, यह स्थापित कानून है कि एक प्रावधान उस प्रावधान से आगे नहीं बढ़ता है जिसके लिए वह एक प्रावधान है। इसलिए, सुनहरा नियम यह है कि प्रावधान समेत पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए कि वे परस्पर एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण हो। यह द्वारका प्रसाद बनाम द्वारका दास सराफ, (1976)1 एसईसी 128 में इस प्रकार निर्धारित किया गया है: -

"18. हम वकील के सामने निष्पक्षता से उल्लेख कर सकते हैं कि अन्य निर्णयों के अलावा, क़ानून में प्रावधानों के उपयोग पर बार में निम्नलिखित का हवाला दिया गया था: सीआईटी बनाम इंडो मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड, [एएलआर 1959 एससी 713: 1959 सप्लिमेंट (2) एससीआर 256 , 266 : (1959) 36 आईटीआर 1] ;

राम नारायण संस लिमिटेड बनाम सहायक सीएसटी [एआईआर 1955 एससी 765 : (1955) 2 एससीआर 483, 493 : (1955) 6 एसटीसी 627] .; थॉम्पसन बनाम डिबडिन [(1912)एसी533 ,541 :81 एलजेकेबी 918: 28 टीएलआर 490];रेक्स बनाम डिबडिन [1910 प्रो डिव 57, 119, 125] और तहसीलदार सिंह बनाम यूपी राज्य [एआईआर 1959 एससी 1012: 1959 सप्लिमेंट (2) एससीआर 875, 893: 1959 सीआरआई एलजे 1231]। कानून घिसा-पिटा है। एक परंतुक अधिनियमित खंड की विषय-वस्तु तक ही सीमित होना चाहिए। यह निर्माण का एक स्थापित नियम है कि एक परंतुक प्रथम दृष्टया पीछे होना चाहिए! और उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिससे वह संबंधित है यह एक प्रावधान है। यह अलग या स्वतंत्र अधिनियमन नहीं है। "शब्द मुख्य अधिनियमित शब्दों पर निर्भर होते हैं जिनमें उन्हें प्रावधान के रूप में जोड़ा जाता है। उन्हें उनके संदर्भ से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता" (थॉम्पसन बनाम डिबडिन, 1912 एसी 533)। यदि निर्माण का नियम यह है कि प्रथम दृष्टया एक प्रावधान को इसके संचालन में अधिनियमित खंड के विषय-वस्तु तक सीमित किया जाना चाहिए, तो हमने जो रुख अपनाया है सही है। प्रावधान द्वारा बढ़ाए गए अधिनियमित खंड का विस्तार करना, निर्माण के मौलिक नियम के खिलाफ पाप है कि एक प्रावधान को मुख्य मामले के संबंध में माना जाना चाहिए जिसके लिए यह एक प्रावधान के रूप में खड़ा है। एक प्रावधान आम तौर पर एक प्रावधान है, हालांकि सुनहरा नियम यह है कि पूरे खंड को, परंतुक

सहित, इस तरह से पढ़ा जाए कि वे परस्पर एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण में परिणत हों।"

21. इस प्रकाश में भी, धारा 47 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और समग्र रूप से पढ़ने पर यह परंतुक से स्पष्ट है कि यह किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए "कार्य के प्रकार" पर लागू होगा और इसलिए, लागू होगा दोनों को रैंक में कमी के साथ-साथ पदोन्नति सहित सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

22. एक और दिलचस्प पहलू धारा 47 और अध्याय VIII के सीमांत नोट से सामने आता है जिसमें धारा 47 आती है। अध्याय VIII का शीर्षक "गैर-भेदभाव" है। साथ ही, धारा 47 का सीमांत नोट "सरकारी नौकरियों में गैर-भेदभाव" है। यह स्पष्ट है कि धारा 47 का विचार सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव करना नहीं है। यह स्थापित कानून है कि भेदभाव को अमूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता- वर्गीकरण का सिद्धांत भेदभाव के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सहायक है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि प्राप्त की जाने वाली वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाला कोई समझदार अंतर है, तो प्रावधान को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि छूट का प्रावधान इस तरह के वर्गीकरण पर आधारित है और किसी भी प्रतिष्ठान को सेवा न देने या रैंक में कमी करने या पदोन्नति न देने से छूट देने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत संबंध है, अर्थात् "कार्य का प्रकार"। किसी प्रतिष्ठान में ऐसा किया जा सकता है कि किसी विकलांग कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं और/या पदोन्नति से इनकार किया जा सकता है।

23. श्री महाबीर सिंह ने इस प्रस्ताव के लिए पेज 345 पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू और अन्य (2003) 3 एससीसी 338 का हवाला दिया कि एक लाभकारी कानून में विधायिका अपने दायरे में आने वाले लोगों के लाभ

के लिए जो देती है, उसे अदालत छीन नहीं सकती है। हमारा विचार है कि यह अधिकार उस मूल कारण पर लागू नहीं होगा जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं लाभकारी कानून में छूट का प्रावधान. हमने पहले ही माना है कि छूट प्रावधान धारा 47 के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करेगा। किन तथ्यों और परिस्थितियों में सरकार किसी प्रतिष्ठान में काम के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग करती है, यह स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है जिसके लिए लाभकारी है छूट की आवश्यकता को संतुलित करने के साथ-साथ कानून बनाया गया हैअधिनियम के एक भाग या संपूर्ण प्रावधानों से कुछ प्रतिष्ठान। वास्तविक निर्माण पर, यह स्पष्ट है कि कानून ने सरकार को किसी भी प्रतिष्ठान को अधिनियम की कठोरता से छूट देने की शक्ति दी है, न केवल पदोन्नति के लिए बल्कि सेवा से समाप्ति और रैंक में कमी के लिए भी, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

24. विद्वान वकील ने हमारे समक्ष कुणाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2003) 4 एससीसी 524 का भी हवाला दिया। इस निर्णय ने निर्णय लिया कि धारा 47 का लाभ एक व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ के रूप में उपलब्ध होगा, भले ही उसे कुछ अन्य लाभ मिलें। उस पर लागू सेवा नियमों के तहत लाभ। उस मामले में अदालत के समक्ष धारा 47 के प्रावधान के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा और वर्तमान विवाद के प्रयोजनों के लिए, उस निर्णय के अनुपात पर बहुत कम या कोई असर नहीं पड़ेगा।

25. अब हम श्री महावीर सिंह द्वारा उठाए गए दो अन्य विवादों पर आते हैं। उनके अनुसार, 1 सितंबर, 2002 की छूट अधिसूचना इस कारण से लागू नहीं होगी कि दुर्घटना 2002 से पहले हुई थी। यह स्पष्ट है कि छूट अधिसूचना उन सभी मामलों पर लागू होगी जिनमें किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसलिए, प्रासंगिक तारीख, सेवा से छूट देने की तारीख है, न कि वह तारीख जिस दिन विकलांगता हुई है, क्योंकि धारा 47 किसी प्रतिष्ठान को ऐसे कर्मचारी की सेवा से छूट देने से रोकती है जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है। चूंकि सेवा 1 जुलाई, 2011 को समाप्त

कर दी गई थी (जो कि छूट अधिसूचना की तारीख के काफी समय बाद है), अधिसूचना, जाहिर है, लागू होगी।

26. श्री महाबीर सिंह द्वारा मांगी गई भेदभाव की दलील उनकी ओर से उत्तर हलफनामे में दिए गए एक कथन पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता (यहाँ प्रतिवादी)। कथन इस प्रकार है:

> "याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि विकलांग व्यक्तियों को सेवा में बनाए नहीं रखा जा रहा है, बिल्कुल गलत है क्योंकि उग्रवादी कार्रवाई आदि के कारण विकलांग हुए व्यक्तियों को बरकरार रखा जाता है और स्थायी आदेश के पैरा 9 (ए) (आई) के अनुसार उन्हें सेवा से अमान्य नहीं किया जा रहा है। सीआरपीएफ की संख्या 7/99 कई विकलांग व्यक्तियों को 1995 के अधिनियम के अधिनियमन और सी.सी.एस. (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 20 (2) में संशोधन के साथ-साथ पारित निर्णय के बाद सीआरपीएफ और अन्य सशस्त्र बलों में बरकरार रखा गया है या बहाल किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा 2003 (2) ईएससी (एससी) कुणाल सिंह बनाम यू.ओ.आई. में रिपोर्ट की गई। यहां तक कि सीआरपीएफ ने भी ऐसे विकलांग अधिकारी श्री प्रताप सिंह को सेवानिवृत्ति तक डिप्टी कमांडेंट बनाए रखा है और श्री वाई.एन. रे और समीर श्रीवास्तव को बनाए रखा है जो विकलांग हो गए थे। सहायक कमांडेंट को नियमित पदोन्नति दी गई और वर्तमान में वे कमांडेंट हैं। दो अन्य अधिकारी श्री आर.के. सिंह और श्री पी.आर. मिश्रा को भी उनकी विकलांगता के बावजूद सेवा में बरकरार रखा गया है। इसी तरह, बीएसएफ ने भी न केवल श्री सुरिंदर सिंह को बरकरार रखा है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिलीप कुमार सिंह 901

[आर.एफ.नरीमन,] लेकिन उन्हें उनकी वर्तमान रैंक सेकेंड इन कमांड तक पदोन्नत कर दिया गया था। भारतीय सेना ने इसी तरह व्हील चेयर पर चलने वाले शारीरिक रूप से अक्षम (लकवाग्रस्त) अधिकारी एस.के. को बरकरार रखा है। राजदान को पदोन्नत किया गया और उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय वायु सेना ने अपने व्हील चेयर पर चलने वाले विकलांग (लकवाग्रस्त) प्रशिक्षु कैडेट हरजोत सिंह को भी बरकरार रखा।"

27. अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे में इस कथन का निम्नलिखित शब्दों में खंडन किया गया है: -

"उत्तर के पैरा 5 (जी-एच) की सामग्री गलत, गलत है और इसलिए अस्वीकार की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वभाव से, नौकरी की आवश्यकताएं "तकनीकी' हैं प्रकृति में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। सीआरपीएफ को अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों से छूट दी गई है। प्रतिवादी स्थायी आदेश 7/99 के दायरे में नहीं आता है और उसे आगे की सेवा के लिए 100% स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया है, उसे सीआरपीएफ मेडिकल मैनुअल की धारा VIII में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया गया था। सामान्य सक्रिय ड्यूटी के लिए उपयुक्त नहीं और 100% स्थायी के बीच अंतर है। आगे की सेवा के लिए असमर्थता. चूंकि प्रतिवादी दूसरी श्रेणी में आता है, इसलिए उसके साथ सीआरपीएफ मेडिकल मैनुअल की धारा VIII में निर्धारित प्रक्रिया के

अनुसार व्यवहार किया गया। हालाँकि, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि भारत संघ बनाम मोहम्मद यासीन अंसारी ((2006) 3 यूपीबीईबीसी 2508] के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले ने माना है कि सशस्त्र बलों में कम विकलांगता वाले व्यक्ति को भी सेवाओं में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

28. उल्लिखित विकलांग अधिकारियों की दलील अस्पष्ट होने के अलावा, उनकी विकलांगता की सीमा के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थायी आदेश संख्या 7/99 लागू नहीं होगा और चूंकि नौकरी की आवश्यकताएं मांग करती हैं उच्च स्तर की योग्यता और क्षमता वाले सीआरपीएफ को अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों से छूट दी गई है। न केवल यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई है, बल्कि हमारे समक्ष उठाई गई याचिका में विवरण की कमी है और इस कारण से भी इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। .

29. हम यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी, जिसने सरकारी आवास पर कब्जा कर रखा है, 30 जून, 2015 तक ऐसे आवास को खाली कर देगा। श्री पटवालिया ने हमें आश्वासन दिया है कि, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, उनसे तब तक कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लिया जाएगा। वह तारीख जिस दिन वह उक्त आवास खाली करता है।

30. अत: अपीलें स्वीकार की जाती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया है. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

कल्पना के त्रिपाठी अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।